फैसला सुरक्षित

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

नैनीताल में

2012 के आदेश संख्या 108 से अपील

मंगत सिंह व अन्य ... अपीलकर्ता

बनाम.

श्री अमित तीरथवाल व अन्य ... उत्तरदाताओं

अधिवक्ताः श्री तपन सिंह, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए

श्री पुलक अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर 3/बीमा कंपनी के लिए

पर आरक्षितः 21.04.2022

पर वितरित : 25.05.2022

माननीय शरद कुमार शर्मा, जस्टिस।

यह एक आदेश से दावेदार अपील है, जिसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए दावेदारों ने 21 दिसंबर 2011 के आक्षेपित निर्णय को आंशिक चुनौती दी है, जिसे एमएसीटी केस नंबर 107/2007 श्री मंगत सिंह तीरथवाल व अन्य बनाम श्री अमित तीरथवाल व अन्य में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/एफटीसी–7/मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा पारित किया गया था।

2. वर्तमान अपील के दावेदारों ने अनुरोध किया था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किए गए आक्षेपित अधिनिर्णय में उनके पक्ष में 9% ब्याज सहित 2,22,000/– रुपये का देय होने का केवल आंशिक निर्णय दिया गया है, जिसे आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से उन्हें देय करने का निर्देश दिया गया है। जिसे दावेदारों द्वारा अपनी दावा याचिका में दावाकृत धनराशि 10.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दावेदार ने अपनी दावा याचिका में दलील दी है जिसे प्रारंभ में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 ए, के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार निचली अदालत में दिनांक 04.05.2007 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में, स्वेच्छा से, दावेदारों द्वारा मांगे गए संशोधन द्वारा, दावा याचिका में संशोधन किया गया और अधिनियम की धारा 163 ए, के तहत दावा याचिका को प्राथमिकता देने के बजाय, इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा– 166 के अन्तर्गत दावा याचिका के रूप में माना जाने के लिए संशोधित किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दो अलग–अलग प्रावधान अर्थात धारा 163ए, जो निम्नानुसार है, इसमें दूसरी अनुसूची में प्रदान किए गए संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के सिद्धांतों के आधार पर

मुआवजे का निर्धारण शामिल है। मोटर यान अधिनियम की धारा 163क में इस प्रकार लिखा है – ''धारा 163ए'' संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान :–

(1) इस अधिनियम में या किसी अन्य विधि में तत्समय लागू किसी बात या विधि बल वाले लिखत में निहित किसी बात के होते हुए भी मोटर वाहन का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता दूसरी अनुसूची में दर्शाये अनुसार विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़िता को जैसा भी मामला हो, मोटर वाहन के प्रयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता के मामले में मुआवजे के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण––इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, ''स्थायी विकलांगता'' का वही अर्थ और सीमा होगी जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के किसी भी दावे में, दावेदार को यह दलील देने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता जिसके संबंध में दावा किया गया है, संबंधित वाहन या वाहन के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कृत्य या उपेक्षा या चूक के कारण थी।

(3) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकेगी। जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 लापरवाही की स्थापना के आधार पर मुआवजे के निर्धारण से संबंधित है, जो निम्नानुसार हैं : –

166. मुआवजे के लिए आवेदन

(1) धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है–

(क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे चोट लगी है, या

(ख) संपत्ति के मालिक द्वारा, या

(ग) जहां दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है, मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा, या

(घ) घायल व्यक्ति या मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा, जैसा भी मामला हो: बशर्ते कि जहां मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि मुआवजे के लिए ऐसे किसी आवेदन में शामिल नहीं हुए हों, वहां आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों और विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा, जो इस प्रकार शामिल नहीं हुए हैं, आवेदन में उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, दावेदार के विकल्प पर, या तो उस दावा अधिकरण में किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, या उस दावा

अधिकरण में जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता रहता है या व्यवसाय करता है या जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी रहता है, जो कि निर्धारित प्रारूप में व निर्धारित विवरणानुसार होगा : बशर्ते कि जहां ऐसे आवेदन में धारा 140 के तहत मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया गया है, आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर से तुरंत पहले उस आशय का एक अलग बयान होगा।

(4) दावा अधिकरण धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन अग्रसारित दुर्घटनाओं की किसी भी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन मुआवजे के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में लेगा।

4. इस प्रकार, जिस स्तर पर दावेदारों ने दावा याचिका दायर की है, उन्होंने संरचित सूत्र को आकर्षित करके उनके द्वारा दावा किए गए मुआवजे के अनुदान के लिए दबाव डाला था, जिसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के प्रावधानों द्वारा लागू किया जाना है। उस स्थिति में, धारा 163 ए के तहत दावा याचिका आगे बढ़ी थी, जिसके तहत, शुरू में इसे स्थापित किया गया था। मुआवजे का निर्धारण द्वितीय अनुसूची में दर्शित मानक के आधार पर संरचित सूत्रों के अनुसार किया जा सकता था।

5. लेकिन, जब दावेदारों ने स्वयं एक संशोधन किया था और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका लाई थी, तो यह उल्लघंन करने वाले वाहन चालक की ओर से, मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा प्रदान करने के लिये मुआवजे की मात्रा और पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों के रंग को पूरी तरह से बदल देता है, जो विशेष रूप से केवल लापरवाही के तथ्य की स्थापना पर अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा तथ्य के निर्धारण और स्थापना पर निर्भर करता है। अतः एक बार जब दावेदारों ने दावा याचिका को धारा 166 के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया है, तो लापरवाही को साबित करने का भार दावेदारों पर स्थानांतरित हो जाता है, जिन्हें मुआवजे के भुगतान की आनुपातिकता निर्धारित करने के लिये उनके द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इसे स्थापित करना पड़ता है।

6. संक्षेप में, जब मुआवजे को धारा 166 के तहत भुगतान करने के लिए बदल दिया गया है और वह भी स्पष्ट रूप से, दावेदारों के स्वैच्छिक कार्य द्वारा, दावेदारों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के तहत प्रदान किए गए संरचित फार्मूले को आकर्षित करने के आधार पर मुआवजे के लिए दावा करने के लिए विबंधित किया जाएगा। 4 मई, 2007 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर किए जाने पर दावेदारों ने तथ्यात्मक रूप से यह दलील दी है कि 20 अप्रैल, 2007 को हुई दुर्घटना में, दावेदार श्री मनोहर लाल नेहरू के पुत्र स्वर्गीय अखिल कुमार तीरथवाल एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार वे

उचित मुआवजे के निर्धारण के हकदार होंगे, जिसका उन्होंने इस आधार पर दावा किया है कि चूंकि उनके दिवंगत बेटे श्री अखिल कुमार तीरथवाल, जो 24 वर्ष के थे और भारतीय सेना में सिपाही के रूप में काम कर रहे थे और वह संबंधित समय हिसार, हरियाणा में तैनात थे। यह तर्क दिया गया था कि वह प्रति माह 11060 रुपये का मासिक वेतन ले रहा था, जो एक संशोधित बढ़ा हुआ वेतन भी था, जो शुरू में 8000 रुपये प्रतिमाह था।

7. दावा याचिका, जिसे दावेदारों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, जिसे दावेदारों द्वारा वर्णित किया गया था, उन्होंने तर्क दिया है कि दुर्घटना की तारीख यानी 20 अप्रैल 2007 को, उनका बेटा, जो वाहन हीरो होंडा मोटरसाइकिल पंजीकरण संख्या यू.ए–07–एन–1082 से एक विवाह समारोह में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था। वह पीछे बैठा था और जिसे एक अन्य व्यक्ति चला रहा था और यह तर्क दिया गया था कि मोटरसाइकिल के सवार यानी अमित तीरथवाल की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण, यह दुर्घटना का शिकार हो गया था, और इसके परिणामस्वरूप श्री अखिल कुमार तीरथवाल की मौत हो गई है।

8. तथ्य यह था कि जब वे वापस लौट रहे थे और गांव बड़ोवाला व भौर के बीच निकट थाना पटेल नगर, जिला देहरादून के पास पहुंचे, अचानक एक दौड़ती हुई गाय सड़क के बीच में आ गई, जिसके कारण वाहन के सवार श्री अमित तीरथवाल, ने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया, उस पर मृतक पीछे बैठा था और चूंकि इसे सवार अमित तीरथवाल द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत मुआवजे के भुगतान की देयता निर्धारित करने की मांग की गई थी, जो कि केवल मोटरसाइकिल के सवार की ओर से लापरवाही की स्थापना पर हो सकती थी।

9. यह तर्क दिया गया था कि जब गाय, अचानक वाहन के सामने आ गई और वाहन के सवार ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, तथा उसने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण मोटरसाइकिल एक खाई में गिर गई जो कि सड़क से सटी हुई थी, जिस कारण मृतक श्री अखिल कुमार तीरथवाल को उक्त दुर्घटना के कारण सिर और शरीर पर आयी हुई चोटों के कारण दुखद मृत्यु का सामना करना पड़ा।

10. दावा याचिका को बीमा कंपनी यानी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पेपर नंबर 15 बी के रूप में अपना लिखित बयान दाखिल करके चुनौती दी थी, इसके अलावा दावा याचिका में उठाए गए दलीलों को खारिज करने के अलावा, उन्होंने तर्क दिया है कि जो कथन किये गये हैं वह बिल्कुल गलत तथ्य है, कि मोटरसाइकिल अमित तीरथवाल द्वारा चलाई जा रही थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है, और आगे उन्होंने इस तथ्य से इंकार किया कि वाहन के सवार के तेजी और लापरवाही से ड्राइविंग

के कारण दुर्घटना हुई है और बल्कि यह मृतक श्री अखिल कुमार तीरथवाल, खुद थे और इसलिए दावेदार खुद मृतक की गलती का फायदा नहीं उठा सकते।

11. बीमा कंपनी द्वारा ली गई अतिरिक्त याचिका में, बीमा कंपनी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि कथित दुर्घटना के समय मृतक, जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं था, इसलिए उत्तर देने वाली बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया कि वे पीछे बैठे व्यक्ति को भी कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

जैसा कि दावा याचिका में कहा गया है, क्योंकि वाहन को वैध दस्तावेज यानी वैध ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तों के तहत नहीं चलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने मुआवजे का भुगतान करने के लिए अपनी देयता से इंकार कर दिया। वास्तव में, यह कथन किये गये थे कि दावा याचिका दोष से ग्रस्त है, उन्होंने यह दलील दी है कि दावा याचिका मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के स्पष्ट दोष से ग्रस्त है, यह दावेदारों और विरोधी पक्ष नंबर 1 और 2 के बीच दुरभिसंधिपूर्वक दायर किया गया है, इसलिए, बीमा कंपनी /प्रत्यर्थी नंबर 3, द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत उठाए जाने वाले अपने बचाव को दावा याचिका का विरोध करने हेतु सुरक्षित रखा गया।

12. दावेदारों ने प्रस्तुत किया कि जब उन्हें 20 अप्रैल 2007 को दुर्घटना की सूचना मिली, कि पीछे बैठे व्यक्ति अर्थात मृतक श्री अखिल कुमार तीरथवाल को गंभीर चोटें आई हैं, तो उन्हें तुरंत अपने इलाज के लिए सीएमआई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान दिनांक 21 अप्रैल 2007 को उनका दुखद निधन हो गया, और 10.00 लाख रुपये के मुआवजे का दावा करने के अलावा, उन्होंने इलाज के खर्च के मुआवजे के लिए भी दावा किया है, जो उन्होंने श्री अखिल कुमार तीरथवाल की मृत्यु से पहले किया था।

13. विपरीत पक्ष नंबर 1 और 2, यानी चालक/सवार और मोटरसाइकिल के मालिक ने पेपर नंबर 6 (बी) के माध्यम से अपना लिखित बयान दाखिल किया था और दावा याचिका में उठाए गए दलीलों के प्रमुख हिस्से से इनकार कर दिया था, लेकिन, हालांकि, उन्होंने केवल इस तथ्य को स्वीकार किया कि दुर्घटना हुई थी, और उस समय जब मृतक प्रश्नगत वाहन पर पीछे बैठे थे और दावा याचिका में वर्णित कहानी के कारण दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण वाहन के सवार ने मोटरसाइकिल पर अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई।

14. कार्यवाही के दौरान और विशेष रूप से, दावेदारों द्वारा किए गए संशोधन के बाद, बीमा कंपनी ने एक अतिरिक्त लिखित बयान यानी पेपर नंबर 39 (बी) दायर किया, जिसमें उन्होंने संशोधन की सीमा और आराम से यह तर्क देते हुए इंकार कर दिया है, कि दावा याचिका जैसा कि दावेदारों द्वारा संशोधित किया गया है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मान्य नहीं होगी और इसलिए संशोधन के कारण, वास्तव में,

दावा याचिका के दाखिले का वाद कारण स्वयं ही अपना महत्व खो चुका है और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163ए के तहत किए जा सकने वाले तुलनात्मक निर्धारण को लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि संशोधन, जिसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किये जाने की अनुमति दी गई थी, लिखित बयान में उठाए गए अनुरोधों पर सुनवाई या आपत्ति उठाने का कोई प्रभावी अवसर प्रदान किए बिना किया गया था और इसलिए उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत निर्धारित दावे से इनकार कर दिया।

15. उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आदान–प्रदान करने के उपरांत, विद्वान मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.07.2008 को निम्न वाद बिंदु निर्धारित किये गये।

1. क्या दिनांक 20.04.2007 को समय लगभग 9 बजे मृतक, अमित तीरथवाल के साथ मोटर साईकिल सं0 यू0ए0–07एन, 1082 में पीछे बैठ कर शादी समारोह से वापस लौट रहा था और रास्ते में ग्राम बडोवाला व भूड बीच अचानक सड़क पर गाय आ जाने के कारण मोटर साईकिल असन्तुलित होकर गड्ढे में जा गिरी जिसके फलस्वरूप मृतक अखिल कुमार के सिर व शरीर के अन्य भागों में चोटें आयी और उपचार के दौरान दिनांक 21.04.2007 को उसकी मृत्यु हो गयी ?

2. क्या दुर्घटना के दिनांक पर मोटर साईकिल चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था ? जैसा कि विपक्षी सं0 3 के प्रतिवाद पत्र में अभिकथित है ?

3. क्या याचीगण कोई क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितनी धनराशि और किस पक्ष से ?

16. वादी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के संबंध में अपनी दलीलों को साबित करने के लिए अपने तर्क के समर्थन में, पेपर नंबर 6 (जीए) के माध्यम से दस्तावेजों की सूची को अभिलेख पर प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार छह दस्तावेजों को अभिलेख पर रखा गया था अर्थात्, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र, मृतक का बीमा कवर नोट और मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा, वादी ने कागज सूची 19 (जीए) द्वारा अभिलेख पर अतिरिक्त चार दस्तावेज प्रस्तुत किये अर्थात् मूल रूप में परिवार रजिस्टर, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा व्यय बिल और मृतक का वेतन प्रमाण पत्र दायर किया था, जो मृतक द्वारा दुर्घटना की तारीख पर प्राप्त की जा रही थी। इसके अलावा, दावेदारों ने गवाहों के रूप में उपस्थित होकर पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 2 के रूप में अपने बयान दर्ज कराए थे और पीडब्ल्यू 3 के रूप में श्री देवेंद्र सिंह चौधरी का मौखिक साक्ष्य भी कराया था। प्रत्यर्थी नंबर 3, यानी बीमा कंपनी ने पेपर लिस्ट नंबर 42 (जीए) के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे, जिसमें बीमा पॉलिसी को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया। लेकिन, हालांकि, निचली अदालत के अभिलेख और दर्ज निष्कर्षों के अनुसार, उन्होंने अपने मामले और दस्तावेजी

साक्ष्य के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया है।

17. विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मामले में कार्यवाही अग्रसारित की और वादबिंदु संख्या 1 पर निर्णय लेते समय, इस संबंध में कि क्या मृतक की मृत्यु 20 अप्रैल 2007 की दुर्घटना के कारण उसे लगी चोटों का परिणामस्वरूप हुई थी या नहीं? विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मौखिक बयान के साथ–साथ अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण करने के बाद पाया था कि दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, मृतक को प्राप्त आय, साथ ही, निर्भरता एक ऐसा तथ्य था जो किसी भी संदेह से परे स्थापित था। और यह भी तथ्य है कि अभिलेख पर दस्तावेजों की आसपास की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दावेदारों के पक्ष में वाद बिंदु संख्या 1 का फैसला किया।

18. वादबिंदु संख्या– 2 पर, वाहन सवार के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के बारे में, जो बीमा कंपनी द्वारा अपने लिखित बयान में उठाया गया विवाद था, दावा याचिका के विरोधी पक्ष/प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा श्री अमित कुमार तीरथवाल के ड्राइविंग लाइसेंस को अभिलेख पर इस तथ्य को स्थापित करते हुए रखा था कि डीएल नंबर 94747/9/2006 वैध रूप से जारी किया गया था और दुर्घटना की तारीख को कानून के अनुसार जीवित था जिसे पेपर नंबर 12 (जीए) के रूप में क्रमांकित किया गया था, जो 23 फरवरी 2006 को उसके पक्ष में जारी किया गया था, इस तथ्य को स्थापित करते हुए कि और परिणामस्वरूप ट्रिब्यूनल ने यह पाया गया कि यह वैध रूप से पंजीकृत था और वैध लाइसेंस के तहत चलाया जा रहा था और उपरोक्त तथ्य के कारण, जब वैध बीमा और वाहन, वैध पंजीकरण के तहत संचालित होने का पता चला, तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सही कहा था कि चूंकि बीमा कवर 05.05.2006 से 04.05.2007 तक वैध था अतः यह 20.04.2007 को वैध था। जब दुर्घटना होती है, तो मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर आ जाती है।

19. वर्तमान अपील में, उपरोक्त तथ्यों के अलावा, दावेदारों द्वारा उत्तेजित विवाद का मूल कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163ए और 166 की तुलनात्मक जांच के दृष्टिकोण से मुद्दे नंबर 3 पर दर्ज निष्कर्षों तक ही सीमित होगा। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कहा है कि जब मुख्य रूप से, दावा याचिका मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के तहत दायर की गई थी और बाद में इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत लाने के लिए दावेदारों द्वारा स्वेच्छा से संशोधित किया गया था, वास्तव में, अधिनियम की धारा 166 के प्रावधान, लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि उस स्थिति में, ड्राइविंग की लापरवाही के तथ्य को साबित करने की आवश्यकता थी और वाहन के सवार श्री अमित तीरथवाल ने इसके विपरीत साबित नहीं किया था, कि वह

दुर्घटना की तारीख पर मोटर साइकिल चलाने में किसी भी तरह से लापरवाही बरत रहा था क्योंकि दुर्घटना एक अजीब परिस्थितियों में हुई थी। गाय के दौड़ने के कारण, सड़क पर आने से सवार ने मोटरसाइकिल पर अपना नियंत्रण खो दिया, इसलिए लापरवाही का तथ्य साबित नहीं हो सका जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत आवश्यक था।

20. लेकिन, फिर भी दावेदार अपने तर्क पर कायम रहा, कि चूंकि बीमा दस्तावेजों जो अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये थे, यह ''पैकेज पॉलिसी'' के अन्तर्गत एक बीमा कवर था, उस स्थिति में, ''पैकेज पॉलिसी'', स्वयं उस तथ्य और परिस्थितियों को कवर करेगी जिसके तहत दुर्घटना हुई थी और दावा याचिका अभी भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत होगी। लेकिन, मुद्दे संख्या 3 पर निर्णय लेने की कार्यवाही के दौरान, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कहा कि बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता की दलील को ध्यान में रखते हुए, धारा 166 के तहत कोई दावा मान्य नहीं होगा और यदि कोई राशि देय थी, तो यह केवल धारा 163ए के तहत हो सकती थी।

21. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने अधिनिर्णयन तर्क दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत, जहां कहीं भी दावा याचिका दायर की जानी है, जो कि मृतक व्यक्ति का बचाव करने के लिए लाभकारी कानून है और चूंकि भारतीय सशस्त्र बलों में काम करने वाले मृतक की मृत्यु 24 वर्ष आयु में हुई थी, धारा 163 ए के अन्तर्गत दावा याचिका लाकर दावा 'कोई दोष रहित दायित्व' के सिद्धांतों द्वारा आच्छादित होगा। विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मृतक की वार्षिक आय 40,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में मानी जानी चाहिए, जिसके आधार पर, अधिनियम की अनुसूची 2 के मानकीकृत सूत्र को लागू करके मुआवजे को निर्धारित किया जा सकता है।

22. माना जाता है, और जो निष्कर्ष दर्ज किए गए थे, उनके अनुसार, यह था कि मृतक अविवाहित था जैसा कि श्रीमती सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य, 2009 (6) एससीसी, 121 में निर्धारित सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया है कि जहां मृतक अविवाहित था, वहां मजदूरी का 50% की कटौती की जानी चाहिए और निर्भरता केवल 50% तक ही सीमित होगी यानी तत्काल मामले में, उस स्थिति में, यह प्रति वर्ष 20,000 रुपये होगा। लेकिन, हालांकि, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दावेदारों यानी मृतक के माता–पिता की उम्र के आधार पर '11' के गुणक को लागू करने की कार्यवाही में कानून में गलती की है और इसलिए गुणक '11' को लागू करके दिया गया मुआवजा अवैध होगा, क्योंकि यदि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अपने तर्क पर धारा 163 ए के तहत निहित सिद्धांतों को लागू किया था, उपस्थिति में घातक दुर्घटनाओं से संबंधित दूसरी अनुसूची के अनुसार, गुणक, जिसे लागू किया जाना चाहिए, '17' होना चाहिए। इस प्रकार '11' के गुणक का अनुप्रयोग अवैध होगा।

23. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेंद्र नाथ लूम्बा और अन्य, 2012 (13) एससीसी 792,** में प्रतिपादित सिद्धांतों से अपने तर्क का समर्थन किया है। और विशेष रूप से, उन्होंने उक्त फैसले के पैरा 2 का संदर्भ दिया है। वास्तव में, यदि पैरा 2 को ध्यान में रखा जाता है, तो यह एक ऐसा मामला था जहां वाहन के चालक के लापरवाही से ड्राइविंग के कारण प्रश्नगत वाहन एक पेड़ से टकरा गया था और दुर्घटना में, दुर्घटना के प्रभाव के कारण कार की विंडस्क्रीन टुकड़ों में टूट गई थी। जो कि दावेदार की आंखों में घुस गया, जो उक्त मामले में पंजाब नेशनल बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था।

24. यदि इसमें निर्धारित अनुपात, धारा 147 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, यह निर्धारित किया गया था कि एक अधिनियम या पॉलिसी, जो तीसरे पक्ष के दायित्व को कवर करती है और न तो पीछे बैठने वाले सवार और न ही सह–यात्री को पीछे बैठने वाले या सह–यात्री को कवर किया जाएगा और देयता बीमाकर्ता की होगी, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 14 में देखा गया है। पैरा 2 और 14 यहाँ से निकाले गए हैं:–

''2. जो तथ्य बताए जाने की आवश्यकता है, वे हैं कि 9.10.1998 को लगभग 4.30 बजे दावेदार, सुरेंद्र नाथ लूम्बा, प्रतिवादी नंबर 3, सविता मट्टा से संबंधित पंजीकरण संख्या डीएल 8 सी –5096 वाली मारुति एस्टीम कार में यात्रा कर रहे थे, और प्रतिवादी नंबर 2, दावेदार के बेटे राज लूम्बा द्वारा संचालित थे। राजपुर रोड स्थित प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड हाउस के पास वाहन एक पेड़ से टकरा गया और दुर्घटना में कार का शीशा टूट गया और उसके टुकड़े दावेदार की आंखों में घुस गए, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपनी दोनों आंखें खो दीं। जैसा कि बताया गया है, दुर्घटना के समय दावेदार पंजाब नेशनल बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था और उसका सकल वेतन 18,949.86 रुपये प्रति माह था और सेवा के साथ विभिन्न अनुलाभ भी जुड़े हुए थे। अपने वेतन और अन्य अनुलाभों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुआवजे के रूप में 18: ब्याज के साथ 62,00,000 रुपये का दावा किया गया। 14. हमने कानूनी स्थिति को दोहराने के लिए विस्तार से उद्धृत किया है। इस मामले में, नीति को अभिलेख पर नहीं लाया गया है। अपीलकर्ता–बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि यह एक ''अधिनियम नीति'' है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता गंभीरता से विवाद करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है या यह ''व्यापक/पैकेज नीति'' हो सकती है। जब बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है लेकिन पॉलिसी को अभिलेख पर नहीं लाया जाता है तो यह केवल यह बताता है कि वाहन का बीमा किया गया है। नीति की प्रकृति को इससे समझा नहीं जा सकता है। इस प्रकार, हम यह सोच

रहे हैं कि मामले को ट्रिब्यूनल में भेजना उचित होगा ताकि बीमाकर्ता पॉलिसी पेश कर सके और पार्टियों को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की स्वतंत्रता दे सके और सलाह के अनुसार आगे के सबूत भी पेश कर सकें, और हम तदनुसार आदेश देते हैं।

25. यदि आक्षेपित पंचाट को सुरेंद्र नाथ लूम्बा (सुप्रा) के पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 14 में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो यह उस व्यक्ति द्वारा साबित करने और निर्वहन करने की आवश्यकता थी, जो बीमा पॉलिसी की व्याख्या करके लाभ का दावा करने की कोशिश कर रहा था, कि यह ''एक्ट पॉलिसी'' या ''व्यापक/पैकेज नीति'' होने के बाद व्यक्ति के अनुदान को अपेक्षाकृत कैसे प्रभावित करेगा। वास्तव में, यदि निर्णय पर विचार किया जाता है, तो दावेदारों द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य से अपनी दलीलों को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया था, विशेष रूप से, जब रिकॉर्ड पर कागज संख्या 42(जीए) के माध्यम से रखे गए दस्तावेजों के अनुसार, बीमा पॉलिसी, और जब बीमा कंपनी द्वारा निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य के हिस्से के रूप में बनाई गई थी, लेकिन नीति को 'अधिनियम नीति', या 'व्यापक नीति/पैकेज नीति' के रूप में निर्धारित करने के लिए किए जा रहे किसी भी प्रयास के अभाव में, सुरेंद्र नाथ लूम्बा (सुप्रा) के निर्णय का लाभ लागू होने के लिए आकर्षित नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक 'व्यापक/पैकेज की गई नीति के लाभ के विस्तार के लिए पूर्व शर्त केवल यह हो सकती है, जब प्रीमियम के सहसंबद्ध भुगतान का तथ्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाता है जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में नेतृत्व किया जाता है।

26. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एक और निर्णय का संदर्भ दिया है, **अमृत भानु शाली और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, 2012 (11) एससीसी 738** में बताया गया है, जहां मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक कार्यवाही में, स्वयं पर व्यक्तिगत खर्चों और माता–पिता की निर्भरता के लिए कटौती के मापदंड शामिल हैं। मृतक की तुलना में, 50 प्रतिशत की कटौती लागू की गई थी, और दावेदारों की आयु के बजाय अधिनियम की अनुसूची के अनुसार मृतक की आयु के आधार पर '17' का गुणक लागू किया गया था।

27. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त फैसले के पैरा 9 का संदर्भ दिया था, जिसमें उक्त मामले में, मृतक की उम्र 29 वर्ष थी और उस समय तक उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन, फिर भी **सरला वर्मा के फैसले (सुप्रा) के** सिद्धांतों के आधार पर, 50 प्रतिशत की कटौती लागू की गई और '17' का गुणक लागू किया गया। उक्त निर्णय का सुसंगत पैरा 9, निम्नानुसार निकाला गया है:–

''वादबिंदु संख्या 2 का निस्तारण करते हुए, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा अपनी जिरह में दिए गए बयान का पालन किया और कहा कि अपीलकर्ता नंबर 3 ममता भानु

शाली को मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता क्योंकि वह लगभग 29 वर्ष की थी और उस समय तक विवाहित थी। शेष अपीलकर्ता नंबर 1 और 2 माता–पिता को आश्रितों के रूप में स्वीकार किया गया था। ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना के समय मृतक अविवाहित और 26 वर्षीय युवक था और उसका वेतन 99,000 रुपये प्रति वर्ष था, आय का 50 प्रतिशत काट लिया और सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम (2009) 6 एससीसी 121 में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार 17 का गुणक लागू किया, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता 66,000/– रुपये का मुआवजा पाने के हकदार हैं। बाकी मुद्दों पर अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला किया गया।

28. '17' के गुणक का अनुप्रयोग, इस तथ्य के अलावा, कि यह **सरला वर्मा के निर्णय** के अनुपात के सिद्धांतों द्वारा समर्थित है, इसे मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची 2 के अनुसार भी लागू किया जाएगा, जिसे दुर्घटना की तारीख को लागू किया गया था जहां '17' का गुणक, मृतक को भुगतान करने पर विचार किया जाता है, जो इसमें प्रदान किए गए आयु स्लैब के भीतर आ रहा है जिसमें वर्तमान मामले के मृतक भी शामिल हैं। इसलिए, न्यायालय का यह विचार है, कि '11' के गुणक के अनुप्रयोग को तदनुसार '17' के गुणक तक बढ़ाया जाना है, और तदनुसार, 20,000/– रुपये प्रति माह की निर्भरता, जिसका मूल्यांकन किया गया है, को '17' के गुणक तक बढ़ाना पड़ा है। इस प्रकार आक्षेपित अधिनिर्णय को इस हद तक संशोधित किया जाएगा कि मुआवजे का निर्धारण '17' के गुणक को लागू करने के बाद किया जाना चाहिए, और तदनुसार, मुआवजे को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

29. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एक और निर्णय का संदर्भ दिया था, जो वास्तव में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में सिद्धांतों से संबंधित था, जहां निर्धारित मुआवजा वैधानिक सूत्र पर नहीं है, जिसे अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत विचार के अनुसार अपनाया जा सकता है। जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए अन्तर्गत प्रस्तुत दावा याचिका में आकर्षित होता है और इसलिए मुआवजे का निर्धारण हमेशा सबूतों पर निर्भर करता है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है या पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिए जैसा कि सुझाव दिया गया है, आम तौर पर जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत दायर दावा याचिका में लागू नहीं किया जायेगा। इस प्रकार दावेदारों द्वारा अनुमानित मामले की समग्र जांच पर, वास्तव में, प्रदान की गई राशि का मूल्यांकन मृतक के दावेदारों/माता–पिता के लिए प्रति माह 2,000 रुपये की वार्षिक निर्भरता के आधार पर किया जाना था और सरला वर्मा के फैसले (सुप्रा) के सिद्धांतों व मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची 2 के आधार पर '17' का गुणक लागू किया जाना है।

30. तदनुसार, आक्षेपित पंचाट को आंशिक रूप से केवल गुणक की प्रयोज्यता की सीमा तक संशोधित किया जाता है जिसे '11' से '17' तक बढ़ाया जाता है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह '17' के गुणक को लागू करने के बाद पंचाट में संशोधन करे और मुआवजे की पर्याप्तता निर्धारित करे।

31. इस प्रकार, आदेश से अपील आंशिक रूप से केवल उस हद तक सफल होती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
25.05.2022

महेन्दर/